3,000 करोड़ रुपये गगनयान का बजट बढ़ाने का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने सुझाव दिया है। बजट में सिर्फ 1,200 करोड़ रुपये का ही आवंटन किया गया है।

'मोदी 55 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में लाए'

- भाजपा अध्यक्ष ने कहा, डब्ल्यूएचओ के आधे लक्ष्य को प्रधानमंत्री ने ही पूरा कर दिया
- डब्ल्यूएचओ ने 100 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में लाने का रखा है लक्ष्य

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को कहा कि 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के आधे लक्ष्य को हासिल करने में अहम योगदान दिया है। डब्ल्यूएचओ ने दुनिया भर में 100 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है।

जन औषधि दिवस के मौके पर पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने कहा कि सरकार का देश भर में 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र खोलने का लक्ष्य है। 20 हजार केंद्र पहले से ही काम कर रहे हैं। इस साल 25 हजार और ऐसे केंद्र खोले जाने हैं।

डब्ल्यूएचओ के लक्ष्य पर उन्होंने कहा कि 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाने का मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही अकेले डब्ल्यूएचओ के 50 फीसद से ज्यादा लक्ष्य को पूरा कर दिया है। इन 55 करोड़ लोगों में से प्रत्येक को इस योजना के तहत पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य लाभ मिलता है। नड्डा ने कहा कि 2014

जेपी नड्डा। फाइल

में जब भाजपा सत्ता में आई थी तब आवश्यक दवाइयों की सूची में मात्र 100 दवाइयां ही थीं, जिनकी कीमतें सरकार द्वारा तय की जाती हैं। मौजूदा समय में ऐसी दवाइयों की संख्या 350 हो गई हैं। आम लोगों के लिए जरूरी दवाइयों को इसके दायरे में लाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

जेनेरिक दवाइयों को लेकर झूठ फैला रहे कुछ लोग

प्रथम पृष्ठ से आगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि जेनेरिक दवाइयों को लेकर अभी भी कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। उन्हें हैरानी होती है कि इतनी सस्ती दवा कैसे मिल सकती है, जरूर इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन आपको देखने के बाद देश के लोगों को यह भरोसा होगा कि जेनेरिक दवाइयों में कुछ भी खराबी नहीं है। ये दवाइयां खराब गुणवत्ता की नहीं हैं। ये दवाइयां भारत में बनी हैं, बेहतर प्रयोगशालाओं में परखी गई हैं और इसलिए सस्ती हैं। उन्होंने कहा कि दुनियाभर में इन दवाइयों की मांग हो रही है।

क्या है जन औषधि केंद्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना शुरू की थी। इसके तहत देश भर में सात सौ से अधिक जिलों में 6,200 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों पर जेनेरिक दवाइयां बहुत कम दाम पर मिलती हैं। इससे लोगों को हर महीने दवा पर औसतन दो से ढाई हजार रुपये बचते हैं। दवा की औसत बाजार कीमत की तुलना में जन औषधि केंद्रों पर 50 से 90 फीसद सस्ती दवाइयां मिलती हैं। उदाहरण के लिए कैंसर के लिए इलाज के लिए जो दवा बाजार में 6,500 रुपये में मिलती है, वही दवा जन औषधि केंद्र पर 850 रुपये में मिल जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में जन औषधि केंद्रों से कुल 390 करोड़ रुपये की दवाइयों की बिक्री हुई।

अभिवादन की भारतीय परंपरा 'नमस्ते' को अपनाएं : प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर फैलाए जा रहे अफवाहों से लोगों को दूर रहने की अपील की और डॉक्टरों की सलाह पर अमल करने को कहा। साथ ही एक दूसरे से मिलने पर अभिवादन के लिए भारतीय परंपरा 'नमस्ते' को अपनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया 'नमस्ते' को अपना रही है। कुछ वजहों से हम इससे दूर हो गए थे, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपनी पुरानी परंपरा को एक बार फिर अपनाएं।

मोदी बोले-ऐसा सुझाव तो नेक दिल इंसान ही दे सकता

राज्य ब्यूरो, जम्मू : आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी इबादत है। औषधीय केंद्रों का लाभ अभी शहरों और मुख्य कस्बों तक ही सीमित है। यही केंद्र अगर गांवों में खुल जाएं तो वहां रहने वाले गरीब लोग भी सस्ते दामों पर इलाज करा पाएंगे। यह बात श्रीनगर के रहने वाले गुलाम नबी बट ने प्रधानमंत्री से वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान कही।

शनिवार को जन औषधि दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जब इन दुकानों में खरीदारी करने वाले मरीजों से बातचीत की तो बट ने यह लाभ गांव-गांव तक पहुंचाने की मांग कर दी क्योंकि अभी ये दुकानें शहरों व मुख्य कस्बों तक ही सीमित हैं। उनके सुझाव से उत्साहित होकर मोदी ने भी उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा सुझाव कोई नेक दिल इंसान ही दे सकता है। इससे पहले गुलाम नबी ने कहा कि पहले वह हर महीने अपनी बीमारी पर 10 हजार खर्च करते था। जब उन्हें यह जानकारी मिली कि सस्ती दवाइयों की सरकारी दुकान खुली है तो वह जन औषधि केंद्र में दवाई लेने पहुंचे। अब वही दवाइयां एक हजार में आती हैं।

आज महिलाओं के हवाले होंगे मोदी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट

नारी शक्ति का सम्मान

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रविवार को 'नारी शक्ति' पुरस्कार से सम्मानित महिलाओं के साथ बातचीत करेंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट भी रविवार को महिलाओं के हवाले होंगे, यानी महिलाएं ही उन्हें चलाएंगी। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने यह जानकारी दी है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार को सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में 'नारी शक्ति' सम्मान से महिलाओं को सम्मानित करेंगे। इसके बाद मोदी इन सम्मानित महिलाओं के साथ बातचीत करेंगे। पीएमओ की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर अकाउंट भी इन्हीं सम्मानित महिलाओं के हाथों में होगा। हर साल 'नारी शक्ति' पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। महिलाओं, खासकर कमजोर और हाशिए की महिलाओं को सशक्त बनाने में उल्लेखनीय योगदान के लिए व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले मंगलवार को कहा था कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनने वाली महिलाओं को वह अपना सोशल मीडिया अकाउंट सौंप देंगे। पीएम ने ट्वीट किया था, 'इस महिला दिवस (8 मार्च) को, मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट को उन महिलाओं को सौंप दूंगा, जिनके जीवन और कार्य हमें प्रेरित करते हैं। इससे उन्हें लाखों लोगों में प्रेरणा प्रज्वलित करने में मदद मिलेगी।'

पीएम के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब प्लेटफार्म पर अकाउंट हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले दुनिया के नेताओं में मोदी शामिल हैं। ट्विटर पर उनके 5.33 करोड़, फेसबुक पर 4.4 करोड़ और इंस्टाग्राम पर 3.52 करोड़ फालोअर हैं। जबकि, पीएमओ के ट्विटर अकाउंट को 3.2 करोड़ लोग फालो करते हैं।

न्यूज गैलरी

पीएफआइ के 21 सदस्यों की जमानत पर रोक

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) के 21 सदस्यों को कर्नाटक हाई कोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगा दी है। पीएफआइ सदस्य कर्नाटक के मंगलुरु में दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा मामले में आरोपित हैं। 17 फरवरी को हाई कोर्ट ने आरोपितों की जमानत मंजूर कर ली थी। आरोपित मुहम्मद आशिक की ओर से दायर अर्जी पर कोर्ट ने यह आदेश दिया था। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने कर्नाटक सरकार द्वारा हाई कोर्ट से मिली जमानत को दी गई चुनौती को संज्ञान में लेने के बाद आरोपित को नोटिस जारी किया। (एएनआइ)

हरिद्वार में तीन कुंभ रेलवे स्टेशन बनेंगे

मुरादाबाद : कुंभ मेला स्थल पर भीड़ भले ही हो, लेकिन स्टेशन पर दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए रेलवे प्रशासन हरिद्वार में तीन कुंभ रेलवे स्टेशन बनाएगा। यहां सभी ट्रेनों का ठहराव होगा। हरिद्वार में जनवरी 2021 से शुरू होने वाले कुंभ मेले में ट्रेनों से दस लाख से अधिक यात्रियों के आने की संभावना है। इसके लिए तीन सौ से अधिक ट्रेनों को चलाया जाना प्रस्तावित है। शनिवार को रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के इसके लिए बैठक की और निर्देश भी दिए। (जासं)

संसद में संग्राम नहीं बहस पर रहेगा विपक्ष का जोर

रणनीति ▸ 11 मार्च को लोकसभा में दिल्ली दंगों पर चर्चा से टूटेगा गतिरोध

अपने सांसदों का निलंबन खत्म कराने की कोशिश करेगी कांग्रेस

संजय मिश्र, नई दिल्ली

संसद के बजट सत्र के पहले हफ्ते हुए घमासान के बाद अगले सप्ताह बदली रणनीति के तहत विपक्षी दल दोनों सदनों में दिल्ली दंगों के साथ अहम मुद्दों पर सदन में बहस के सहारे सरकार की घेराबंदी करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस के सात सांसदों के निलंबन को लेकर सरकार से जारी तनातनी के बावजूद विपक्ष दिल्ली दंगों की चर्चा में इस विवाद को आड़े नहीं आने देगा।

विपक्षी खेमे की रणनीति में बदलाव की एक वजह होली के बाद पहले कार्यदिवस को ही दिल्ली दंगों पर चर्चा कराने की सरकार की घोषणा है। बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला हफ्ता विपक्ष और सरकार की जिद में धुल गया। दिल्ली दंगों पर सबसे पहले चर्चा की मांग से विपक्ष पीछे नहीं हटा तो सरकार भी होली के बाद ही चर्चा कराने के रुख पर अडिग रही। इसी घमासान के दौरान गुरुवार को लोकसभा में कांग्रेस के सात सांसदों को निलंबित भी किया गया जिसने तल्खी और बढ़ा दी।

हालांकि कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि निलंबन की कार्रवाई से पक्ष-विपक्ष के बीच बढ़े तनाव के बावजूद दोनों सदनों में मुद्दों पर बहस ही विपक्षी पार्टियों के हित में है। हंगामे को लंबा खींचा गया तो सरकार उलटे इसे विपक्ष के खिलाफ प्रचारित करेगी। इसीलिए दिल्ली दंगों पर 11 मार्च को बहस शुरू होती है तो फिर विपक्ष को सदन चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार ने लोकसभा में 11 मार्च और राज्यसभा में 12 मार्च को दिल्ली दंगों पर चर्चा की बात कही है। जहां तक कांग्रेस सांसदों के निलंबन को वापस लेने का सवाल है तो वह स्पीकर ओम बिड़ला की अगुआई वाली कमेटी की जांच के बाद ही होगा। निलंबन को सदन चलाने के गतिरोध से अलग रखने का संकेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भी दिया। दिल्ली दंगों पर लोकसभा में 11 मार्च को बहस के बारे में पूछे जाने पर चिदंबरम ने तंज कसते हुए कहा 'मैंने भी सुना है कि संसद में इस पर बहस हुई है पर पता चला कि यह ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुआ है। इसीलिए उम्मीद है कि इस पर गौर करते हुए संसद के दोनों सदनों के हमारे पीठासीन अधिकारी दंगों के मामले पर चर्चा कराएंगे।'

विपक्षी दलों की सदन में बहस को वरीयता देने की रणनीति के पीछे तर्क यह भी है कि केवल दिल्ली दंगे ही नहीं बल्कि यस बैंक संकट और आर्थिक मंदी से लेकर सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई, कश्मीर के हालात जैसे अहम मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरा जा सके। संसद में कांग्रेस के एक प्रमुख रणनीतिकार का तो यह भी कहना था कि इस सरकार में विपक्षी दलों की बात किसी प्लेटफार्म पर न सुनी जा रही और न ही दिखाई जा रही है। ले देकर संसद ही वह मंच है जिसके जरिये विपक्ष अपनी बात जनता तक पहुंचा सकता है। इसीलिए अब विपक्ष की ओर से संग्राम कम और बहस पर जोर ज्यादा रहेगा।

सरकार ने एशियानेट न्यूज, मीडिया वन से प्रतिबंध हटाया

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने मलयालम के दो समाचार चैनलों के प्रसारण पर शुक्रवार को लगाया गया 48 घंटे का प्रतिबंध शनिवार को हटा लिया। यह प्रतिबंध ऐसी खबरें प्रसारित करने के लिए लगाया गया था कि इससे देश में 'सांप्रदायिक विद्वेष' को बढ़ावा मिल सकता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि एशियानेट न्यूज पर लगा प्रतिबंध देर रात डेढ़ बजे जबकि मीडिया वन पर लगी रोक को शनिवार सुबह साढ़े नौ बजे हटा लिया गया। दिल्ली में पिछले महीने हुए सांप्रदायिक दंगों पर दी गई खबरों को लेकर इन चैनलों के प्रसारण पर 48 घंटे की रोक लगाई गई थी।

बाद में पुणे में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि केंद्र ने प्रतिबंध हटा लिया है और सरकार प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करती है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वह मामले को देखेंगे और जरूरत पड़ी, तो आवश्यक कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे मुद्दे पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने मीडिया के लिए जिम्मेदारियों के साथ स्वतंत्रता की वकालत की।

एशियानेट न्यूज के संपादक एमजी राधाकृष्णन ने कहा कि उनके चैनल के प्रबंधन ने प्रतिबंध लगाए जाने के बाद मंत्रालय से संपर्क किया था और संबंधित लोगों से बात की थी। दूसरी तरफ, मीडिया वन के प्रधान संपादक सीएल थॉमस ने कहा कि उनका चैनल सरकार के पास नहीं गया और मंत्रालय ने स्वतः प्रतिबंध हटाया है। उन्होंने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई का रुख कर रहे थे। आज हमें सूचना मिली कि प्रतिबंध हटा लिया गया है। इसलिए हम कानूनी कार्रवाई की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। हमने मंत्रालय में किसी से संपर्क नहीं किया। हम खुश हैं कि मंत्रालय ने स्वतः हटा लिया। हम पत्रकारिता के उत्कृष्ट मूल्यों का पालन करने और उन्हें बरकरार रखने की राह पर चलना जारी रखेंगे।

कांग्रेस और वामदलों ने की आलोचना : चैनलों पर प्रतिबंध लगाए जाने की कांग्रेस और वाम दलों ने आलोचना की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया कि इस अपमानजनक फैसले के खिलाफ व्यापक आक्रोश के बाद सरकार को बुद्धि आई है। आजादी के लिए हमें हर दिन संघर्ष करना चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है और आने वाले खतरों का संकेत है। सरकार ने अपनी सभी सीमाओं का उल्लंघन करते हुए प्रेस की आजादी पर हमला किया है। इस बात का डर है कि यदि कोई आरएसएस और संघ परिवार की आलोचना करेगा, तो उसे सबक सिखाया जाएगा। राजधानी दिल्ली में पत्रकारों ने जंतर-मंतर पर केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के बैनर तले प्रदर्शन किया।

बैंक कर्ज लेकर फरार आरोपित को मस्कट से लाया गया

नई दिल्ली, प्रेट्र : बैंक से 10 करोड़ रुपये कर्ज लेकर फरार हो गए आरोपित सन्नी कालरा को सीबीआइ ओमान के मस्कट से शनिवार को देश लेकर आई। सीबीआइ ने 2016 में अनुरोध किया था और उसके आधार पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। उसी नोटिस के आधार पर उसे प्रत्यर्पित किया गया है। आरोप है कि व्हाइट टाइगर स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक कालरा ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 10 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, लेकिन उसने उसका भुगतान नहीं किया। अधिकारियों ने बताया कि उसने चोरी छिपे गिरवी की चीज निकाल ली जिस कारण सरकारी बैंक के लिए इस कर्ज की वसूली मुश्किल हो गई। उन्होंने बताया कि कालरा, उसकी पत्नी और अन्य के खिलाफ इस मामले को 16 दिसंबर 2015 को सीबीआइ ने अपने हाथ में लिया।

सीबीआइ प्रवक्ता ने कहा, 'दोनों (कालरा और उसकी पत्नी) प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद से फरार थे।' एजेंसी ने कालरा, उसकी पत्नी और पीएनबी के तीन अधिकारियों के खिलाफ इस मामले को हाथ में लेने के एक साल से अधिक समय बाद 22 दिसंबर, 2016 को आरोपपत्र दायर किया। अधिकारियों ने बताया कि इंटरपोल ने सीबीआइ के अनुरोध पर 31 मार्च 2016 को कालरा के खिलाफ 'रेड कॉर्नर नोटिस' जारी किया था।

यस बैंक संकट का आरबीआइ करे जांच : चिदंबरम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस ने यस बैंक संकट को राजग सरकार के दौरान वित्तीय संस्थाओं में जारी घोर कुप्रबंधन का नतीजा बताया है। साथ ही रिजर्व बैंक से यस बैंक संकट की गहन जांच कर बैंकिंग व्यवस्था की विश्वसनीयता बहाल करने को कहा है। पार्टी ने यस बैंक के लोन में बीते पांच साल खासकर नोटबंदी के बाद हुए भारी इजाफे पर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए सवाल उठाया कि रिजर्व बैंक और सरकार की दोहरी ऑडिट व्यवस्था इसे कैसे नहीं पकड़ पाई।

पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम और कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि बैंकों के नाकाम होने की घटनाओं से बैंकिंग व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था जो पहले से ही कई चुनौतियों से जूझ रही है, वह हमारे वित्तीय संस्थाओं के इस तरह गिरते साख की वजह से ज्यादा गंभीर हो रही है। इसलिए बैंकिंग व्यवस्था में विश्वसनीयता बहाल करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले रिजर्व बैंक यस बैंक के संकट की गहराई से जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करे।

निशाना

- बैंकों पर लोगों का भरोसा बहाल करने के लिए तय हो जवाबदेही
- सरकार व आरबीआइ की ऑडिट व्यवस्था विफल, हिस्सेदारी से बेहतर होगा एसबीआइ करे यस बैंक का अधिग्रहण

नई दिल्ली में शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने प्रेसवार्ता के दौरान यस बैंक मामले की जांच कर बैंकिंग व्यवस्था की विश्वसनीयता बहाल करने की मांग की। प्रेट्र

चिदंबरम ने यस बैंक के लोन में सालाना 35 फीसद के इजाफे को हैरतअंगेज बताते हुए कहा कि इस आंकड़े के बावजूद रिजर्व बैंक और सरकार के बैंकिंग ऑडिट की आंख नहीं खुलना आश्चर्यजनक है। 2014 के बाद खासकर नोटबंदी के पश्चात के दो सालों में बैंक के लोन दर पर तंज कसते हुए चिदंबरम ने कहा कि यस बैंक कर्ज दे नहीं बल्कि लुटा रहा था। उन्होंने सवाल उठाया कि रिजर्व बैंक में क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है? सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि दिसंबर 2019 तक बैंकिंग सेक्टर की कुल 16,88,600 करोड़ रुपये की पूंजी क्षीण हो चुकी है। 2014 के बाद 7,78,000 करोड़ रुपये का बैंक कर्ज माफ हुआ है। दिसंबर 2019 तक बैंकों का कुल एनपीए 9,10,800 करोड़ रुपये पहुंच गया है। छोटी व मझोली कंपनियों (एसएमई) के कर्ज पर लगी पाबंदी मार्च के अंत में जब खत्म होगी तो यह आंकड़ा कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। मुद्रा योजना के तहत दो लाख करोड़ रुपये का लोन माफ हुआ है और 17000 करोड़ रुपये का एनपीए है। कांग्रेस नेता ने यह भी सवाल उठाया कि बैंक के सालाना बैलेंस सीट को क्या रिजर्व बैंक और सरकार दोनों ने नहीं देखा? जब जनवरी 2019 में बैंक का सीईओ बदला गया और रिजर्व बैंक के एक डिप्टी गर्वनर को यस बैंक बोर्ड में शामिल किया गया उसके बाद कोई बदलाव नहीं हुआ। यहां तक की मई 2019 में जब यस बैंक ने पहली बार अपने तिमाही घाटे की घोषणा की तभी खतरे की घंटी सरकार और रिजर्व बैंक को सुनाई नहीं दी।

यस बैंक मामले में कांग्रेस नेता का अजीब बयान, हिंदू खतरे में

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यस बैंक के संकट पर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस संकट में वास्तव में हिंदू खतरे में पड़े हैं, ऐसा नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने दावा किया कि यस बैंक के ज्यादातर खाताधारक हिंदू हैं, इसलिए वही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के भी बैंक में 545 करोड़ रुपये जमा हैं। इस लिहाज से भगवान भी संकट में हैं और केंद्र सरकार यह सब देख रही है। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को यस बैंक को अपने कब्जे में ले लिया और अब उससे 50 हजार रुपये की निकासी की सीमा तय कर दी है। सावंत ने कहा, भाजपा और उसके सहयोगी संगठन अक्सर हिंदुओं के खतरे में होने की बात कहते रहते हैं। ऐसा वह राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए कहते हैं। जबकि वास्तव में बैंक डूबने से हिंदू खतरे में पड़ा है और मोदी सरकार के आंखों के सामने यह सब हुआ है।

राणा कपूर से पूछताछ, बेटियों के घर भी छापे

राज्य ब्यूरो, मुंबई

शुक्रवार रात यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के घर से शुरू हुई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच शनिवार को उसकी बेटियों और परिवार के अन्य सदस्यों तक पहुंच गई। राणा कपूर को शनिवार को ईडी कार्यालय में बुलाकर भी करीब सात घंटे पूछताछ की गई और प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत उसका बयान रिकॉर्ड किया गया।

ईडी ने शुक्रवार रात राणा कपूर के वरली स्थित आवास पर जाकर उससे पूछताछ की थी। शनिवार को उसे बेलार्ड पियर्स स्थित ईडी कार्यालय बुलाकर पूछताछ की गई। जांच का दायरा बढ़ाते हुए उसकी तीन बेटियों राखी कपूर टंडन, रोशनी कपूर और राधा कपूर के दिल्ली और मुंबई स्थित घरों पर भी छापेमारी की गई और उनसे पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार ईडी को पता चला है कि यस बैंक से लिए गए भारी-भरकम कर्ज के बदले दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) ने राणा कपूर के परिवार की एक कंपनी को 600 करोड़ का कर्ज दिया था। ईडी कुछ ऐसी कंपनियों के बीच हुए करीब 5,000 करोड़ रुपयों के लेनदेन की भी जांच कर रहा है जो या तो राणा कपूर के परिवार की थीं या हैं अथवा डीएचएफएल से जुड़े लोगों की रही हैं। यस बैंक द्वारा डीएचएफएल को दिया गया भारी-भरकम कर्ज उसके द्वारा चुका नहीं पाने के कारण एनपीए हो गया था।

डीएचएफएल के खिलाफ जांच से जुड़ा है मामला

मुंबई, एजेंसियां : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डीएचएफएल के खिलाफ अपनी जांच के क्रम में ही राणा कपूर के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है। डीएचएफएल के खिलाफ मामले में जांच एजेंसी को पता चला था कि एक लाख फर्जी कर्जदारों का इस्तेमाल करके 12,500 करोड़ रुपये 80 मुखौटा कंपनियों में स्थानांतरित किए गए थे। इन मुखौटा कंपनियों में ये लेनदेन 2015 में किए गए थे। दिल्ली में एक ईडी अधिकारी ने बताया कि डीएचएफएल के खिलाफ जांच के दौरान पता लगा कि उसने जो धनराशि स्थानांतरित की थी उसका स्रोत यस बैंक था। राणा कपूर के घर मारे गए छापे और रातभर की गई पूछताछ का मकसद यस बैंक द्वारा डीएचएफएल को दिए गए कर्ज में बरती गई अनियमितता का पता लगाना था। ईडी ने डीएचएफएल के कपिल और धीरज वधावन पर पांच फर्मों - फेथ रियल्टर्स, मार्वेल टाउनशिप, अबे रियल्टी, पोसीडॉन रियल्टी और रेंडम रियल्टर्स के शेयर खरीदने और उन्हें सनब्लिंक में मिलाने का आरोप लगाया है। उक्त पांचों फर्मों पर जुलाई, 2019 तक 2,186 करोड़ रुपये का कर्ज था। डीएचएफएल से हासिल कर्ज को छिपाने के लिए इन पांचों फर्मों पर बकाया कर्ज को कथित रूप से सनब्लिंक के अकाउंट्स में दर्शाया गया था। इसके अलावा एक मामला उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन में कथित पीएफ धोखाधड़ी से जुड़ा है।

जमा हैं महाराष्ट्र के तीन नगर निकायों के 1,125 करोड़

मुंबई, आइएएनएस : महाराष्ट्र के तीन बड़े नगर निकायों के करीब 1,125 करोड़ रुपये यस बैंक में जमा हैं। पिंपरी-चिंचवाड़ नगर निगम (पीसीएमसी), नासिक नगर निगम (एनएमसी) और नासिक नगर स्मार्ट सिटी विकास निगम लिमिटेड (एनएमएससीडीसीएल) ने स्वीकार किया है कि उनके क्रमशः 800, 310 और 15 करोड़ रुपये यस बैंक में जमा हैं।

सुरक्षा

केवल जिंक के बजाय अब जिंक-एल्यूमीनियम मिश्रण की होगी कोटिंग, आरडीएसओ ने बनाए मानक, रेलवे बोर्ड ने जोनों, रेल निर्माताओं को दिए निर्देश

अब और ज्यादा सुरक्षित होंगी रेल की पटरियां

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पटरियों के क्षरण के कारण दुर्घटनाओं से हैरान रेलवे ने भविष्य में पटरियों पर अकेले जिंक के बजाय जिंक व एल्यूमीनियम के मिश्रण से कोटिंग का निर्णय लिया है। इससे पटरियां ज्यादा दिनों तक चलेंगी और उनमें फ्रैक्चर भी कम होंगे। इन पटरियों का उपयोग खासकर तटीय इलाकों में होगा, जहां क्षारीय मौसम व आर्द्रता के कारण पटरियां जल्दी क्षतिग्रस्त होती हैं। रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स आर्गनाइजेशन (आरडीएसओ) की ओर से इस मिश्रण की कोटिंग के मानक तय किए जाने के बाद रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलों और रेल निर्माताओं को इसके उपयोग की हरी झंडी दे दी है।

भारतीय रेल लंबे अरसे से पटरियों के क्षरण की समस्या से जूझ रही है। इस वजह से न केवल पटरियां समय से पहले अपनी दृढ़ता खो देती हैं, बल्कि इससे उनमें फ्रैक्चर और उस कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। इस समस्या से निपटने के लिए 2005 में रेलवे बोर्ड ने पटरियों पर जिंक मेटलाइजेशन (कोटिंग) करने का निर्णय लिया था। 2006 में आरडीएसओ ने इसके मानक भी तय कर दिए थे। इसके तहत उत्पादन के बाद पटरियों पर जिंक की मूल परत के बाद चार ऊपरी परतें और चढ़ाई जाती थीं।

परंतु वक्त के साथ यह तकनीक पुरानी पड़ गई है, क्योंकि विकसित देशों में रेल मेटलाइजेशन को ज्यादा टिकाऊ बनाने के लिए अकेले जिंक के इस्तेमाल के बजाय जिंक व एल्यूमीनियम के मिश्रण (85 फीसद जिंक व 15 फीसद एल्यूमीनियम) का उपयोग होने लगा है। इस तकनीक की लागत भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें केवल एक सतह की कोटिंग करने की जरूरत पड़ती है। जिंक-एल्यूमीनियम कोटिंग की खास बात यह है कि पटरी की क्षरण प्रक्रिया के दौरान केवल इसी ऊपरी परत को क्षति पहुंचती है, जबकि भीतर का स्टील ज्यों-का-त्यों सुरक्षित बना रहता है। माकूल उपकरणों से सुसज्जित रेलवे वर्कशॉप

प्रतीकात्मक।

में प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा इलेक्ट्रिक आर्क स्प्रे व ब्लास्टिंग इक्विपमेंट इत्यादि की सहायता से रेल पटरियों पर आसानी से कोटिंग की जा सकती है।

विशेष स्टील से निर्मित इन पटरियों की आयु सामान्यतया 12 वर्ष होती है। परंतु क्षरण के कारण ये अक्सर दो-तीन सालों में ही अपनी दृढ़ता खोने लगती हैं। इससे इनमें दरारें पड़ने लगती हैं, जो ट्रेन दुर्घटनाओं का बड़ा कारण हैं। इससे बचने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 2018 में ट्रैक नवीकरण की राष्ट्रव्यापी मुहिम शुरू की थी। इसके तहत हर साल 4,000 किमी से ज्यादा पटरियों को बदला जा रहा है। 2018-19 में 4,181 किमी ट्रैक का नवीकरण हुआ था। 2019-20 में भी 31 मार्च तक 4,000 किमी से ज्यादा ट्रैक नवीकरण की उम्मीद है।

क्षरण के कारण रेलवे को हर साल करीब चार हजार किलोमीटर पटरियों को बदलकर नई पटरियां बिछानी पड़ती हैं। इस पर लगभग पांच हजार करोड़ रुपये का खर्च आता है। इस भारी खर्च के कारण ही रेल मंत्रालय ने अब पटरियों को क्षरण रोधी बनाने पर अधिक ध्यान देने का निर्णय लिया है। एक अनुमान के अनुसार, पटरियों पर जिंक-एल्यूमीनियम कोटिंग के लिए लगभग 1.20 लाख टन जिंक और 21 हजार टन एल्यूमीनियम की आवश्यकता होगी। इस पर लगभग 2,000 करोड़ का ही खर्च आएगा। फिलहाल रेलवे स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अलावा जिंदल स्टील से पटरियों की खरीद कर रही है। इनसे भी नई पटरियों में जिंक-एल्यूमीनियम कोटिंग करने को कहा गया है।

कह के रहेंगे माधव जोशी